भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1508
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

सहकारी आंदोलन को मजबूती

1508. **श्री कंवर सिंह तंवरः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), दुग्ध सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), भंडारण संस्थाओं तथा आम, गन्ना और दुग्ध आधारित गतिविधियों में मूल्य संवर्धन के संबंध में सहकारी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कृषि यंत्रीकरण सेवाओं तथा सहकारी आंदोलन के डिजिटलीकरण की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिले में आधुनिकीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), सुदृढ़ की गई सहकारी समितियों, पूर्ण की गई कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिले में विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त जिले में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहकारी ऋण, भंडारण सुविधाओं, किसानों की भागीदारी तथा विपणन सहायता को विस्तृत करने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जिले में सहकारी नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा चिन्हित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में, सहकारी अवसंरचना को सशक्त करने, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने, सहकारी कार्यों को डिजिटल बनाने और मूल्यवर्धन की सुविधा के लिए कई उपाय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 27.24 लाख रुपये की लागत से तीन एम-पैक्स, शाहपुर कलां, सिहरा और तिगरी में गोदामों की मरम्मत और आधुनिकीकरण पूरा किया गया। डिजिटलीकरण के लिए, 45 सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकरण के लिए चुना गया है, जबकि सभी एम-पैक्स में क्यूआर-कोड-आधारित उर्वरक भुगतान शुरू किया गया है। यह इन

समितियों को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है क्योंकि वे किसानों के लिए बहु-सेवा केंद्र और वन-स्टॉप शॉप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, जिले की सभी सहकारी समितियों के डेटा को एनसीडी (राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस) पोर्टल पर अपडेट किया गया है ।

अमरोहा जिले में दुग्ध सहकारी समितियों को दुग्ध की गुणवत्ता और समय के आधार पर भुगतान किया जाता है। ये समितियां किसानों को पशु चारा, दवाएं, खनिज मिश्रण और सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए अन्य इनपुट मुफ्त में वितरित करती हैं और दुग्ध उत्पादकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत नई समितियों का गठन किया गया है, जिसमें डिजिटल प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (डीपीएमसीवी) प्रणाली की स्थापना के लिए प्रति नवगठित समिति को 36,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

जिले में 32 कार्यशील किसान उत्पादक संगठन हैं, जिनमें से 14 एफपीओ ने 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की है, जिससे लघु और सीमांत किसान सस्ती दरों पर कृषि उपस्कर किराए पर ले सकते हैं। ये एफपीओ बड़े पैमाने पर सरकारी सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त कृषि मशीनरी का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से, एक एफपीओ को 80% सब्सिडी पर इन-सीटू योजना के तहत मशीनरी प्रदान की गई है ।

मूल्यसंवर्धन के क्षेत्र में, अमरोहा को मुरादाबाद डिवीजन के भीतर आम-फलपट्टी (मैंगो फ्रूट बेल्ट) क्षेत्र के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आम की खेती लगभग 12,000 हेक्टेयर में की जाती है, जिसका उत्पादन लगभग 2,05,560 मीट्रिक टन होता है, और इसे संयुक्त अरब अमीरात, रूस और यूनाइटेड किंगडम (लंदन) सहित बाजारों में निर्यात किया जाता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग अपने कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें किसान पंजीकरण और सब्सिडी को प्रक्रियाबद्ध करना शामिल है।

गन्ना क्षेत्र में, अमरोहा में सहकारी गन्ना विकास समितियों ने किसानों को ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, टिलर, रोटावेटर और पावर स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि उपस्कर प्रदान करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की है। गन्ना भूखंड सर्वेक्षण, स्मार्ट गन्ना किसान (एसजीके) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से आयोजित किया जाता है, जबकि ड्रोन का उपयोग ड्रोन दीदी योजना के तहत कीट और रोग प्रबंधन के लिए और जंगली जानवरों से संबंधित फसल क्षति का पता करने के लिए किया जाता है। ये समितियां विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा, सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों को ई-गन्ना प्रणाली के तहत कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिससे किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल सर्वेक्षण, आपूर्ति पर्ची और भुगतान की स्थिति पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकें ।

अमरोहा जिले में 45 सहकारी समितियों को राष्ट्रीय पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत कवर किया गया है । कंप्यूटरीकृत पैक्स को कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण नागरिक, स्थानीय स्तर पर 300 से अधिक सरकारी और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सकें।

पैक्स को जिले में राष्ट्रीय सहकारी और केंद्र सरकार की पहलों से जोड़ा जा रहा है, जिसमें सस्ती दवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुंच के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की सदस्यता शामिल है । इसके

अलावा, 10 चयनित एम-पैक्स को उनके व्यवसाय प्रचालन और वित्तीय क्षमता को सशक्त करने के लिए "सहकार से समृद्धि" पहल के तहत 10 लाख रुपये की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।

(ग): ऊपर दी गई सूचना के अलावा, अमरोहा में प्रमुख कृषि और सहकारी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय उपयोग का ब्योरा **संलग्नक -क** में संलग्न है।

(घ) और (ड.): अमरोहा जिले में 45 सहकारी समितियां किसानों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर फसली ऋण प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, 5,111 सदस्यों को ₹473.57 लाख की राशि के ऋण वितरित किए गए । जिले में 8,575 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण क्षमता है, जो सहकारी संस्थानों के माध्यम से सुरक्षित भंडारण और वितरण की सुविधा प्रदान करती है।

धान और गेहूं का प्रापण पीसीएफ और पीसीयू के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के तहत किया जाता है। वर्ष 2026-27 के दौरान, 5,000 मीट्रिक टन के जिला लक्ष्य के मुकाबले, 3,650.100 मीट्रिक टन गेहूं का प्रापण किया गया है, जो लक्ष्य का लगभग 73 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 के दौरान, योजना के तहत कुल 2,375 मीट्रिक टन का प्रापण किया गया था ।

सहकारी नेटवर्क को और सशक्त करने के लिए कालाखेड़ा और हसनपुर में दो नए एम-पैक्स स्थापित किए गए हैं। एम-पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुंच और कॉमन सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सरकारी सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में भी उत्तरोत्तर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, महा-सदस्यता अभियान के तहत, 2024-25 के दौरान 31,323 नए सदस्यों और वर्ष 2025-26 के दौरान 15,720 नए सदस्यों का नामांकन किया गया, जिससे जिले में सहकारी संस्थानों के सदस्यता आधार का विस्तार हुआ।

***

संलग्नक -क

वित्तीय सहायता और उपयोग का विवरण (अमरोहा जिला)

(सभी आंकड़े ₹ में हैं)

क्रम सं.	कार्यक्रम/कार्यकलाप	प्राप्त/व्यय	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1.	**जिला योजना (जिला योजना)**				
1.1	आधार पौधशाला बीज वितरण	प्राप्त	443,950	560,000	610,700
		व्यय	443,950	560,000	610,700
1.2	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण	प्राप्त	1,929,075	2,210,000	2,448,950
		व्यय	1,929,075	2,210,000	2,448,950
1.3	अभिजनक बीज यातायात	प्राप्त	13,290	14,655	12,405
		व्यय	13,290	14,655	12,405
1.4	आधार बीज यातायात	प्राप्त	63,994	78,400	80,066
		व्यय	63,994	78,400	80,066
1.5	बीज/ भूमि उपचार कार्यक्रम	प्राप्त	3,416,400	3,550,500	3,680,100
		व्यय	3,416,400	3,550,500	3,681,000
1.6	जैव-उर्वरक वितरण	प्राप्त	1,200,000	1,243,800	941,400
		व्यय	1,200,000	1,243,800	941,400
1.7	वानीकिये विज्ञान	प्राप्त	-	-	4,080
		व्यय	-	-	4,080
2.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**				
2.1	आधार पौधशाला बीज वितरण	प्राप्त	533,300	451,100	116,600
		व्यय	533,300	451,100	116,600
2.2	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण	प्राप्त	4,234,275	3,902,500	833,350
		व्यय	4,234,275	3,902,500	833,350
2.3	क्षेत्र प्रदर्शन	प्राप्त	1,017,000	945,000	504,000

		व्यय	1,017,000	945,000	504,000
2.4	सूक्ष्म पोषक तत्व	प्राप्त	1,172,500	778,500	583,500
		व्यय	1,172,500	778,500	583,500
2.5	ग्रामीण महिला उन्नत गन्ना बीज वितरण	प्राप्त	501,183	1,026,415	145,540
		व्यय	501,183	1,026,415	-
2.6	किसान मेला	प्राप्त	-	-	100,000
		व्यय	-	-	-
3.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना**				
3.1	अंतर-फसल (दलहन और तिलहन) प्रदर्शन	प्राप्त	990,000	450,000	360,000
		व्यय	990,000	450,000	-
3.2	कृषि रक्षा रसायन और सूक्ष्मजीव	प्राप्त	47,000	23,000	17,500
		व्यय	47,000	23,000	-

नोट:- वर्ष 2026-27 के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) के लिए व्यय स्पर्श पोर्टल के माध्यम से किया जाना था; तथापि, तकनीकी कारणों से व्यय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।